जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 293 प्रभात चूरू, बुधवार 19 फरवरी, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

क्या अपने कूटनीतिक फायदे के लिए अमेरिका, यूक्रेन वॉर खत्म करना चाहता है

और इसके लिए रूस की शर्त मानने और किसी भी हद तक जाने को तैयार है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 फरवरी। रूसी राष्ट्रपति, व्लादिमीर पुतिन, पहले ही अपनी कूटनीति से एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं और वह है यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करना।

अपनी घोषित मंशा के तहत अमेरिका, यूक्रेन युद्ध को तुरंत समाप्त करने के लिए, रूस के साथ अकेले वार्ता करने जा रहा है, यूरोपीय देशों को शामिल किए बिना। इससे यूरोपीय देशों को झटका लगा है।

यदि युद्ध दोनों प्रमुख वार्ताकारी वर्तमान वार्ता की स्थिति के आधार पर समाप्त होता है, तो यह एक पूरी तरह से नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत करेगा। यह जिसकी "लाठी उसकी भैंस" कहावत को चरितार्थ करेगा। जबकि पूर्व वैश्विक व्यवस्था कानून के शासन और देशों की संप्रभुता का सम्मान करती थी।

जबकि यूक्रेन का भविष्य सऊदी अरब में आयोजित वार्ताओं में तय किया जा रहा है, पर यूक्रेन इसमें शामिल नहीं है और किसी भी वार्ता से बहुत दूर है। चूँकि, नए अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पुनरारंभ पर यूक्रेन युद्ध को तुरंत समाप्त करने का वादा किया था, इसलिए रूस वार्ता में अपनी बात मनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

- रूस की पहली शर्त है कि यूक्रेन संबंधी वार्ता में ब्रिटेन व यूरोपियन यूनियन को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि वे रूस विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं। रूस की यह शर्त मान ली गई है, क्योंकि सऊदी अरब में हो रही यूक्रेन वार्ता में सिर्फ रूस व अमेरिका ही बैठेंगे। यहाँ तक कि यूक्रेन को भी अलग रखा गया है।
- रूस की एक और शर्त है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ैलैंस्की इस्तीफा दें तथा युद्ध के खत्म होने के बाद यूक्रेन से दूर हो जाए। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन के जिन चार क्षेत्रों की 75 प्रतिशत जमीन पर कब्जा कर लिया है, वे यूक्रेन के क्षेत्र पूरी तरह से रूस को सौंप दिए जाएं।
- रूस की एक अन्य शर्त यह है कि यूक्रेन का निशस्त्रीकरण किया जाए और उसे नाटो में शामिल न किया जाए।
- ज्ञातव्य है कि इनमें से कोई भी शर्त यूरोपियन यूनियन व ब्रिटेन को स्वीकार नहीं है। क्योंकि अगर इन शर्तों के आधार पर युद्ध समाप्त हुआ तो इससे "जिसकी लाठी उसकी भैंस" कहावत की पुष्टि होगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि सऊदी अरब की राजधानी में युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि, यूएन में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने ऐसी शर्तें रखी हैं जो यूक्रेन के लिए स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं।

उनकी पहली शर्त यह है कि यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम की यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की वार्ता में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। रूस के राजदूत ने कहा कि यूरोपीय संघ और यूके के पास शुरु से ही रूसी विरोधी भावना से ग्रस्त हैं और इसलिए वे किसी भी वार्ता का हिस्सा नहीं हो सकते।

नेबेंजिया ने यह भी कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जैलेन्स्की को इस्तीफा देना होगा और युद्ध समाप्त होने के बाद या वार्ताओं में यूक्रेन से संबंधित किसी भी मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

तीसरी शर्त यह है यूक्रेन रूस को उन क्षेत्रों का और ज्यादा भाग सौंपेगा जो पहले से रूस के अधीन है, इनमें वे चार क्षेत्र हैं, जिनका 75 प्रतिशत से ज्यादा भाग रूस के कब्जे में है।

अंत में, रूस ने यह आग्रह किया है कि यूक्रेन का निशस्त्रीकरण किया जाना चाहिए और उसे नाटो गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। ऐसी किसी भी शर्त को स्वीकार करना यूक्रेन या उसके वर्तमान सहयोगियों, अर्थात् यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के लिए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेज रफ्तार डंपर ने लोडिंग ऑटो को टक्कर मारी, 6 की मौत

भिंड, 18 फरवरी। मध्यप्रदेश के भिंड जिले में भिंड-इटावा मार्ग पर जवाहरपुरा गांव के पास आज सुबह डंपर की टक्कर से लोडिंग वाहन सवार छह लोगों की मौत हो गयी और बीस अन्य घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार लोडिंग ऑटो में सवार एक दर्जन से अधिक लोग विवाह समारोह के बाद जवाहरपुरा गांव से भवानीपुरा गांव लौट रहे थे, तभी जवाहरपुरा गांव के पास यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े लोडिंग ऑटो को टक्कर मार दी। दुर्घटना में पांच लोगों की मौके पर मौत हो गयी,

- विवाह समारोह में भाग लेकर अपने गाँव लौटने के लिये लोग लोडिंग ऑटो में बैठ रहे थे, जब यह टक्कर हुई।

जबकि एक की ग्वालियर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। हादसे में घायल हुए 20 लोगों का इलाज किया जा रहा है। दुर्घटना के बाद डंपर चालक मौके से भाग निकला। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और हाइवे को सिक्सलेन बनाने की मांग करते हुए कलेक्टर, एसपी और सांसद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश की जा रही है।

बताया जा रहा है कि जवाहरपुरा निवासी राकेश जाटव के बेटे की शादी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

4340 करोड़ रूपए की घोषित आय के साथ भाजपा सब से अमीर पार्टी

भाजपा की कुल आय 5 राष्ट्रीय दलों की संयुक्त इन्कम से भी ज्यादा है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 फरवरी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 4340.473 करोड़ रूपए की घोषित आय के साथ, भाजपा ने आय के मामले में अन्य राजनैतिक पार्टियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। विस्मित कर देने वाली भाजपा की आय पाँच राष्ट्रीय दलों की कुल आय की तीन गुना से भी अधिक है। जहाँ भाजपा का यह वित्तीय प्रभुत्व चन्दा प्राप्त करने की उसकी अद्भुत क्षमता पर प्रकाश डालता है, वहीं, यह भारत की राजनैतिक निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, भाजपा ने अपनी कुल आय का केवल 50.96 प्रतिशत ही खर्च किया है। "इलैक्शन वॉचडॉग," एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिव रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने 2,211.698 करोड़ रूपए खर्च किये हैं।

रिपोर्ट कहती है कि इसी अवधि के दौरान, कांग्रेस की कुल आय 1,225.119 करोड़ रूपए रही तथा उसने 1025.248 करोड़ रूपए खर्च किये। इस प्रकार, कांग्रेस का खर्च उसकी कुल आय का 83.69 प्रतिशत था।

- एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट में विभिन्न राजनैतिक दलों के वित्त वर्ष 23-24 के आय-व्यय का ब्यौरा दिया।
- रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने अपनी कुल आय का 50.96 प्रतिशत, यानि 2,211.698 करोड़ रूपए खर्च किए।
- रिपोर्ट कहती है, कांग्रेस की कुल आय 1225.119 करोड़ रूपए रही, वहीं पार्टी ने इसका 83.65 प्रतिशत, यानि की 1024.248 प्रतिशत खर्च किया।

भाजपा और कांग्रेस के अलावा, अन्य चार राष्ट्रीय दल इस प्रकार हैं- बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी तथा नैशनल पीपुल्स पार्टी। एडीआर रिपोर्ट, आय-व्यय की उस विवरणिका पर आधारित होती है, जिसकी घोषणा राजनैतिक दल अपनी उन वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट्स में करते हैं, जो भारत के चुनाव आयोग में पेश की जाती हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, जहाँ बसपा, एनपीईपी तथा आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट गत वर्ष 31 अक्टूबर, जो रिपोर्ट पेश करने की अंतिम तिथि थी, से पहले ही पेश कर दी थीं, माकपा (सी.पी.एम.), कांग्रेस तथा भाजपा ने अपनी रिपोर्ट क्रमशः 12 दिन, 53 दिन तथा 66 दिन के विलम्ब से पेश की थीं।

वित्त वर्ष 2023-24 में, माकपा की कुल घोषित आय 167.636 करोड़ रूपए थी, जिसमें से पार्टी ने 127.283 करोड़ रूपए खर्च किये थे, जो कुल आय का लगभग 75 प्रतिशत थे। बसपा की कुल आय 64.7798 करोड़ रूपए थी तथा इसका खर्च 43.189 करोड़ रूपए था, जो उसकी आय का लगभग 66 प्रतिशत था।

वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच, भाजपा की आय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मुस्लिम कर्मचारी रमज़ान में चार बजे घर जा सकेंगे'

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रैवन्त रेड्डी के इस आदेश ने कांग्रेस को मुश्किल में डाला

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 फरवरी। क्या तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने शासन करने के तरीके से पार्टी की मदद कर रहे है या पार्टी का नुकसान कर रहे हैं।

देश की कुछेक कांग्रेस सरकारों में से एक तेलंगाना सरकार ने तो बजट पेश किया था वो सिर्फ बजट नहीं बल्कि गवर्नेंस का मॉडल था, जिसे कांग्रेस बतौर उदाहरण पेश कर सकती थी, खासकर भाजपा की आलोचना के जवाब में लेकिन उसी तेलंगाना सरकार ने पार्टी पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण करने वाली पार्टी का ठप्पा लगा दिया। तेलंगाना सरकार ने भाजपा को खुद ऐसा मुद्दा थमा दिया है जिसका वह कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है।

तेलंगाना सरकार ने आदेश निकाला है कि राज्य सरकार के व सरकारी निकायो व पी.एस.यू. के मुस्लिम कर्मचारी रमज़ान के महीने में शाम को एक घंटा पहले घर जा सकते हैं। इस आदेश ने भारी विवाद खड़ा कर दिया है। अन्य धर्मों के लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है कि उन्हें भी अपने त्यौहारों पर ऐसी छूट चाहिए।

सरकार के आदेश में लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 2 मार्च से 31 मार्च के बीच 4 बजे ऑफिस छोड़ सकते हैं। स्पष्ट रुप से इस कदम का लक्ष्य है कि मुसलमानों को रमजान के महीने में नमाज के लिए छूट्टी देना है।

पर अब भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया है और कांग्रेस के खिलाफ अपने पुराने मसले को और तेज बनाकर प्रयुक्त कर रही है भाजपा का कहना है कि कांग्रेस हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों का तुष्टिकरण कर रही है।

भाजपा विधायक राजा सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ऐसे कदम और कुछ नहीं बल्कि उसकी तुष्टिकरण राजनीति का चरम है। राजा सिंह ने पूर्व में आरोप लगाया था कि कांग्रेस मुसलमान वोटों को तवज्जो देने के कारण जीती हैं।

- तेलंगाना सरकार के इस आदेश पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा और कहा, यह ही है कांग्रेस का असली चेहरा, मुस्लिम तुष्टिकरण।
- भाजपा नेताओं व कई हिंदू संगठनों ने इस निर्णय की आलोचना की और कहा कि ऐसी छूट हिंदू त्योहारों पर क्यों नहीं दी जाती।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एचएआई अतिक्रमण हटाने की दैनिक रिपोर्ट 25 को पेश करे

जयपुर, 18 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर हाईवे पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में एनएचएआई की ओर से अतिक्रमण हटाने की धीमी कार्रवाई को लेकर नाराज़गी जताई है। अदालत ने कहा, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एनएचएआई ने 90 दिन में 90 अतिक्रमण ही हटाए हैं। इसके साथ ही, अदालत ने एनएचएआई को कहा कि वे मौके से हटाए जाने वाले अतिक्रमण की दैनिक आधार पर रिपोर्ट तैयार करें और

- हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया, अजमेर हाईवे पर एनचनआई ने 90 दिन में केवल 90 अतिक्रमण हटाये।

आगामी 25 फरवरी को अदालत में पेश करें। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस मनीष शर्मा ने ये आदेश रायचंद चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से कहा गया कि हाईवे और सर्विस लेन की जमीन को एनएचएआई को सुपुर्द किया जा चुका है। ऐसे में जो भी अतिक्रमण है, वह एनएचएआई की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'महाकुंभ, मृत्युकुंभ में बदल गया है,' ममता बनर्जी ने कहा

भाजपा ने कहा, हिंदू विरोधी हैं, प.बंगाल की मुख्यमंत्री

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 फरवरी। अगले वर्ष होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच लड़ाई जोर पकड़ती दिखाई देने लगी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि भगदड़ की घटनाओं के कारण, महाकुंभ ने "मृत्युकुंभ" का रूप ले लिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस धार्मिक आयोजन के दौरान, मरने वालों की वास्तविक संख्या अधिकारियों द्वारा दबा दी गई है।

भाजपा ने बनर्जी के इस बयान पर तत्काल पलटवार किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायकों ने मंगलवार को तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन किया तथा इस समय चल रहे महाकुंभ मेले के बारे में उनकी "मृत्युकुंभ" वाली टिप्पणी को लेकर उन्हें "हिन्दू-विरोधी मुख्यमंत्री" की संज्ञा दी।

- ममता बनर्जी ने प.बंगाल विधानसभा में प्रयागराज में हुई भगदड़ और उसमें हुई मौतों को मुद्दा बनाया व कहा कि सरकार ने सैंकड़ों शव छिपा लिए ताकि मौतों की संख्या कम दिखाई जा सके। भाजपा सरकार की अव्यवस्था ने महाकुंभ को मृत्युकुंभ में बदल दिया।
- ममता बनर्जी की इन टिप्पणियों पर विपक्षी दल भाजपा ने भारी नारेबाजी की और उन्हें हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा कि "महाकुंभ" जैसे पवित्र अवसर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।

पिछले माह, उत्तर प्रदेश के महाकुंभ नगर प्रयागराज में कम से कम 30 लोग मर गये थे तथा 60 लोग घायल हो गये थे। इसके अलावा, अभी हाल ही में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जमा भारी भीड़ में भगदड़ के कारण 18 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुये, ममता बनर्जी ने कहा, "महाकुंभ ने "मृत्युकुंभ" का रूप ले लिया है। मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूँ। मैं गंगा माँ का सम्मान करती हूँ। लेकिन (इस अवसर पर) योजना जैसी कोई चीज नहीं है। ..... धनवान लोगों तथा वीआईपी लोगों के लिये एक लाख रूपए तक के कैम्प प्राप्त करने की व्यवस्था है। गरीबों के लिये कुंभ में कोई इंतजाम नहीं है।..... किसी भी "मेला" में भगदड़ की स्थिति एक सामान्य बात है। लेकिन व्यवस्था करना जरूरी एवं महत्वपूर्ण होता है। आपने क्या योजना बनाई थी?"

राज्य विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान बनर्जी ने कहा, "मरने वालों की संख्या कम दिखाने के लिये सैकड़ों लाशें छिपा दी गई हैं। भाजपा शासन में, महाकुंभ "मृत्युकुंभ" में तब्दील हो गया है।"

बनर्जी ने महाकुंभ में हुई भगदड़ को "अत्यन्त हृदय-विदारक" बताया तथा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ी धार्मिक भीड़ वाले अवसरों पर बेहतर योजना एवं प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "जब लोगों की सुरक्षा की बात आती है तो ऐसी घटनाओं के दौरान हुईं दुखद मृत्यु सोच-समझ कर बनाई गई योजनाओं की महत्ता दर्शाती हैं।

ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात के लिये भी आलोचना की कि सरकार ने "उचित व्यवस्थाएं किये बिना" महाकुंभ को लेकर अति प्रचार-प्रसार पर ज्यादा ध्यान दिया।

उन्होंने कहा, "महाकुंभ में हुई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुजरात निकाय चुनावों में भाजपा की भारी जीत

अहमदाबाद, 18 फरवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में भाजपा ने सभी 10 नगर निगम जीते थे। अब गुजरात के निकाय चुनाव में भी भाजपा का डंका बजा है। मंगलवार को आए नतीजों ने बीजेपी को गदगद कर

- 68 में 60 नगर पालिकाओं पर भाजपा ने जीत हासिल की, कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन सपा का रहा, उसने 2 नगर पालिकाएं जीतीं।

दिया। गुजरात की 68 नगर पालिकाओं में से 60 पर भाजपा ने जीत हासिल करते हुए पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बधाई संदेश लिखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

यूक्रेन वॉर पर यूरोप की एकता में दरार डाल रहा है अमेरिका

यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बिना रूस से समझौता की वार्ता कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रम्प

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 फरवरी। यूक्रेन युद्ध के प्रति यूरोपियन प्रतिक्रिया को एकजुट रखने वाला अमेरिका अब उस एकता को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ डॉनल्ड ट्रंप युद्ध को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं यूरोपीय नेता और नीति निर्माता चिंतित हैं कि वाशिंगटन की ताज़ा रणनीतियाँ महाद्वीप को विभाजित कर रही हैं।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने पिछले हफ्ते यूरोप की अपनी पहली यात्रा में मित्र व सहयोगी राष्ट्रों के बीच मतभेद की विवादास्पद स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने खुले तौर पर अतिवादी दक्षिणपंथी नेताओं को गले लगाया, यूरोप के खनिज संसाधनों तक पहुंच की मांग की, और ऐसी सहानुभूतियाँ व्यक्त कीं, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दृष्टिकोण के साथ मेल खाती थीं। सप्ताह के अंत तक, यूरोपीय नेता रूस के साथ शांति वार्ता से बाहर किए जाने की चिंताजनक संभावना का सामना कर रहे थे। इसके अलावा, उन्हें वाशिंगटन के साथ ट्रेड वॉर का खतरा और यूक्रेन में युद्धविराम लागू करने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को भेजने के दबाव का सामना भी करना पड़ा, जबकि, युद्ध विराम के निर्णय में यूरोपीय नेताओं की कोई भागीदारी नहीं थी।

ट्रंप की नीति ने उन लोगों में भारी चिंता पैदा कर दी है, जो लंबे समय से अमेरिका-यूरोप गठबंधन के समर्थक रहे हैं। दशकों तक, द्वितीय युद्ध के बाद, वाशिंगटन ने यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद की और राष्ट्रों के बीच आपसी संघर्षों को रोकने के लिए यूरोपीय संघ को प्रोत्साहित किया। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप के कदम अब इन प्रयासों को नष्ट कर रहे हैं, क्रैमलिन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और सैन्य बल द्वारा क्षेत्रीय विवादों को निपटाने के खतरे फिर से बढ़ा रहे हैं।

इसके अलावा, यूक्रेन या यूरोपियन नेताओं से परामर्श किए बिना पुतिन के साथ ट्रंप की सीधे, 90 मिनट की बातचीत ने चिंता को और बढ़ा दिया। बातचीत के बाद, उनके द्वारा दिए गए बयान से आभास हुआ कि वे रुस के इस दावे को वैध ठहरा रहे हैं कि नाटो का एक्सपैंशन (विस्तार) यूक्रेन पर रुस के आक्रमण को सही ठहराता है, जो अमेरिका की वर्षों पुरानी नीति के खिलाफ है।

ट्रंप के सहयोगियों का कहना है कि उनकी रणनीति विभाजन पैदा करने के बारे में नहीं, बल्कि आवश्यक बदलावों को लेकर है। ट्रंप के विशेष दूत कीथ कैलॉग ने उनकी रणनीति की तुलना चिकित्सीय प्राथमिक उपचार से की: "पहले, आप खून बहना रोकते हैं, फिर शॉक का इलाज करते हैं।" उनका तर्क है कि इस संघर्ष को केवल यूरोपीय समस्या के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक लड़ाई के रूप में देखा जाना चाहिए।

तथापि, यूरोपीय अधिकारियों का कहना है कि मनमाने ढंग से ट्रंप का निर्णय लेने का तरीका, उन गठबंधनों को खत्म कर रहा है, जो बहुत मुश्किल से बने थे। जिन लोगों ने उनके प्रशासन के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी, उनका विश्वास भी कमज़ोर हुआ है। उदाहरण के लिए, यूक्रेन और रूस पर महीनों तक कैलॉग के साथ काम करने के बाद, यूरोपीय कूटनीतिज्ञों को यह जानकर हैरानी हुई कि ट्रंप ने उन्हें हटा कर अपने व्यक्तिगत मित्र स्टीव विटकॉफ को क्रैमलिन के साथ महत्वपूर्ण बातचीत के लिए नियुक्त कर दिया।

नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री रूबेन ब्रीकलमैन्स ने एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "हमें तानाशाही के खतरों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, लोकतंत्र पर लड़ने के बजाय। हमारी ताकत एकता में है।"

डैनमार्क की प्रधानमंत्री मेता फ्रेदरिक्सन ने ट्रंप के रुख के व्यापक परिणामों के बारे में चिंता व्यक्त की। "हम सक्रिय युद्ध में लिप्त नहीं हो सकते, लेकिन निश्चित रूप से यह शांति का समय नहीं है। यह एक वास्तविक खतरा है कि रूस को छूट देने का कोई भी समझौता उसे फिर से हथियारों के पुनः निर्माण और अपनी आक्रामकता जारी रखने की अनुमति देगा, चाहे वह यूक्रेन में हो या कहीं और।"

- विशेषज्ञों का कहना है, ट्रम्प का यह कदम क्षेत्रीय विवाद निपटाने में सैन्य बल के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा। यूरोपियन यूनियन को आशंका है कि ट्रम्प के इस रुख से रूस को अन्य देशों के खिलाफ सैन्य बल प्रयुक्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने कहा कि ट्रम्प का निर्णय लेने का तरीका नाटो को भी विघटित कर सकता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था तथा रूस के विरूद्ध हमेशा खड़ा रहा था।

सत्येन्द्र जैन पर मनी लॉन्डरिंग का केस चलेगा

नई दिल्ली, 18 फरवरी। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद आज आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप नेता सत्येन्द्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चालने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दे दी है। ईडी अब राष्ट्रपति की मंजूरी की जानकारी देते हुए एक नया पूरक आरोप

- राष्ट्रपति मुर्मू ने आप सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ केस चलाने की प्रवर्तन निदेशालय को अनुमति दी।

पत्र अदालत में दाखिल करेगा। बता दें कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मंजूरी मांगी थी।

गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और पर्याप्त सबूतों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)